

ऊर्जा के लिए साम्राज्यवादी लालच

निकोलास मदुरो लंबे समय से तर्क देते रहे हैं कि वेनेजुएला की पीड़ा और फिलिस्तीनी संघर्ष अलग-अलग त्रासदियां नहीं हैं, बल्कि एक ही वैश्विक अपराध की अभिव्यक्तियां हैं: ऊर्जा की अतृप्त भूख से प्रेरित साम्राज्यवादी वर्चस्व। भाषण दर भाषण, मदुरो ने उस साझा भाग्य की निंदा की जिसे उन्होंने अमेरिका समर्थित आक्रमण द्वारा थोपा गया बताया—जिसमें संप्रभु लोगों को स्वायत्तता से वंचित किया जाता है, नाकाबंदियों के अधीन किया जाता है, और वैश्विक शक्तियों द्वारा वांछित संसाधनों के स्वामित्व के लिए दंडित किया जाता है। इतिहास ने अब उनकी चेतावनी को सही ठहराया है। वेनेजुएला और फिलिस्तीन अमेरिका की जीवाश्म ईंधनों—तेल, गैस और ऊर्जा नियंत्रण की लालची खोज के समानांतर शिकार के रूप में खड़े हैं—किसी भी कीमत पर।

वेनेजुएला और फिलिस्तीन: एक साझा साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा

वेनेजुएला का फिलिस्तीन के साथ गठबंधन केवल बयानबाजी का नाटक या कूटनीतिक अवसरवाद नहीं था। यह चाविज़्मो का एक आधारभूत स्तंभ था, जो हूगो शावेज़ से विरासत में मिला और मदुरो के अधीन कायम रहा। 2013 में सत्ता संभालने के बाद से, मदुरो ने लगातार फिलिस्तीन के कब्जे को वेनेजुएला की खुद की घेराबंदी से अविभाज्य बताया, जो प्रतिबंधों और दबाव के अधीन थी। वेनेजुएला ने 2009 में इज़राइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए, गाजा संकटों के दौरान मानवीय सहायता पहुंचाई, और इज़राइली कार्रवाइयों को अमेरिकी शक्ति द्वारा सक्षम अपराधों के रूप में निंदा की।

मदुरो ने बार-बार गाजा को सामूहिक दंड का प्रयोगशाला बताया—जिसकी तुलना उन्होंने वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों द्वारा थोपी गई आर्थिक गला घोटने से की। उन्होंने वाशिंगटन और उसके सहयोगियों पर गाजा में “नरसंहार” सक्षम करने और कराकास के खिलाफ “आर्थिक आतंकवाद” छेड़ने का आरोप लगाया। 2024 के एक संबोधन में, उन्होंने फिलिस्तीनी संघर्ष को “मानवता का सबसे पवित्र कारण” घोषित किया, इसे स्पष्ट रूप से वेनेजुएला के अमेरिकी प्रयासों के खिलाफ प्रतिरोध से जोड़ा, जो उसके तेल संपदा पर नियंत्रण हथियाने के थे।

इन चेतावनियों को आलोचकों ने वैचारिक दिखावा बताया। फिर भी घटनाओं ने उन्हें भयावह रूप से दूरदर्शी साबित कर दिया है। मदुरो ने तर्क दिया कि संसाधन-संपन्न राष्ट्रों पर केवल दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें लक्ष्य बनाया जाता है—प्रतिबंधों, छद्म युद्धों और प्रत्यक्ष बल के माध्यम से—जब तक कि अनुकूल शासन स्थापित न हो जाएं। फिलिस्तीन में, उन्होंने गाजा की नाकाबंदी को फिलिस्तीनियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण से वंचित करने की जानबूझकर रणनीति बताया, जिसमें गाजा मरीन गैस क्षेत्र शामिल है। वेनेजुएला में, यही तर्क तेल पर लागू होता है। जीवाश्म ईंधन वैश्विक शक्ति के लिए केंद्रीय बने रहने के बावजूद ऊर्जा संक्रमण की बयानबाजी के बावजूद, अमेरिकी हस्तक्षेपवाद तीव्र हुआ है, मदुरो के विश्लेषण को जीवंत वास्तविकता में बदल दिया है।

वेनेजुएला: अपनी तेल की रक्षा करने के लिए दंडित

वेनेजुएला की विशाल प्राकृतिक संपदा ने इसे लंबे समय से विदेशी शिकार के लिए चिह्नित किया है। दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार—300 अरब बैरल से अधिक—मुख्य रूप से ओरिनोको बेल्ट में केंद्रित, देश एक ऐसा पुरस्कार है जिसे ऊर्जा-भूखी शक्तियां अनदेखा नहीं कर सकतीं। मदुरो के अधीन, राज्य तेल कंपनी PDVSA ने अमेरिकी कॉर्पोरेट वर्चस्व का प्रतिरोध किया, इसके बजाय रूस, चीन और ईरान के साथ साझेदारी की, जैसे काराबोबो और जुनिन परियोजनाओं का विकास।

जवाब था आर्थिक युद्ध। 2017 से शुरू होकर, अमेरिकी प्रतिबंधों ने व्यवस्थित रूप से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को अपंग कर दिया, तेल उत्पादन को लगभग 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से एक मिलियन से नीचे ला दिया। मदुरो ने इन प्रतिबंधों को लोकतंत्र संवर्धन के उपकरण नहीं, बल्कि चोरी के साधन बताया—वेनेजुएला को अधीनता में धकेलने और उसके तेल क्षेत्रों को अमेरिकी नियंत्रण के लिए खोलने के लिए डिज़ाइन किए गए।

यह उद्देश्य स्पष्ट हो गया 5 जनवरी 2026 को, जब अमेरिकी सैन्य हमलों ने कराकास को निशाना बनाया और निकोलास मदुरो को पकड़ लिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन को “नार्को-आतंकवाद” के खिलाफ अभियान बताया, लेकिन उनके अपने शब्दों ने किसी बहाने को छीन लिया। मार-ए-लागो में बोलते हुए, ट्रंप ने घोषणा की: “हम देश चलाएंगे जब तक कि हम सुरक्षित, उचित और न्यायोचित संक्रमण कर सकें।” उन्होंने जोर दिया कि वेनेजुएला का अमेरिकी प्रशासन “हमें एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा,” क्योंकि तेल राजस्व—“जमीन से निकलने वाला पैसा”—अमेरिकी प्रयासों की भरपाई करेगा।

यह कोई विसंगति नहीं थी। यह एक परिचित साम्राज्यवादी स्क्रिप्ट का अनुसरण करता था, इराक और लीबिया की गूंज, जहां शासन परिवर्तन ने ऊर्जा पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया। मदुरो की बर्खास्तगी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रमण के रूप में निंदा हुई, ने वर्षों से उनकी चेतावनियों की पुष्टि की: वेनेजुएला का तेल इसे लक्ष्य बनाता है। ट्रंप की संसाधन निकासी पर बेशर्म fixation ने हस्तक्षेप को उजागर किया—सुरक्षा नीति के रूप में छिपा ऊर्जा हड़पना।

गाजा मरीन: फिलिस्तीन का चोरी किया गया भविष्य

फिलिस्तीन का अनुभव उसी तर्क का अनुसरण करता है। 2000 में, गाजा मरीन गैस क्षेत्र की खोज हुई, जो तट से लगभग 36 किलोमीटर दूर है, जिसमें अनुमानित एक ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस है। वैश्विक मानकों से मामूली होने के बावजूद, यह क्षेत्र फिलिस्तीनी ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए जीवनरेखा का प्रतिनिधित्व करता है। UNCLOS के तहत फिलिस्तीनी समुद्री क्षेत्रों में स्थित, गाजा मरीन को गाजा की अर्थव्यवस्था को बदल देना चाहिए था।

इसके बजाय, विकास को गला घोट दिया गया। इज़राइली प्रतिबंधों, सैन्य नियंत्रण और चल रहे कब्जे ने फिलिस्तीनियों को उनके संसाधनों तक पहुंच से रोका। समर्थक तर्क देते हैं कि इज़राइल की नाकाबंदी और बार-बार सैन्य अभियान—संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कूटनीतिक और सैन्य समर्थन प्राप्त—केवल सुरक्षा उद्देश्यों की सेवा नहीं करते, बल्कि आर्थिक भी: फिलिस्तीनियों को उनकी प्राकृतिक संपदा पर संप्रभुता से वंचित करना।

अक्टूबर 2023 के युद्ध के बाद से, ये चिंताएं तीव्र हुई हैं। आरोप बढ़े हैं कि गाजा में बड़े पैमाने पर विस्थापन इज़राइली शोषण को सुविधाजनक बना सकता है गाजा मरीन का, इसे अमेरिकी समर्थन से क्षेत्रीय ऊर्जा नेटवर्क में एकीकृत करके। 2023 में इज़राइल द्वारा आसपास के जलों में अन्वेषण लाइसेंस जारी करना, साथ ही मिस्र के साथ \$35 अरब का गैस निर्यात सौदा, जानबूझकर संसाधन चोरी के दावों को ईंधन देता है। इस प्रक्रिया में, अमेरिका ने इज़राइल को कूटनीतिक रूप से ढाल दिया, संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों को वीटो किया और लेवांत बेसिन में ऊर्जा सुरक्षा को फिलिस्तीनी अधिकारों पर प्राथमिकता दी।

वेनेजुएला के साथ समानता स्पष्ट है। दोनों मामलों में, प्रतिबंध, नाकाबंदियां और बल स्थानीय आबादी को उनके संसाधनों से लाभ से रोकते हैं, जबकि बाहरी शक्तियां खुद को लाभ के लिए स्थिति में रखती हैं।

कानून टूट गया

वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप और ट्रंप के अपने बयान अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानून के तहत गंभीर परिणाम उठाते हैं।

कब्जे के अधीन वेनेजुएला

ट्रंप द्वारा खुलकर घोषणा करके कि अमेरिका संक्रमण काल के दौरान वेनेजुएला “चलाएगा”, उन्होंने कब्जे की कानूनी स्थितियां स्थापित कीं। 1907 हेग विनियमों के अनुच्छेद 42 के तहत, कब्जा तब अस्तित्व में होता है जब क्षेत्र शत्रु सेना के अधिकार के अधीन रखा जाता है जो प्रभावी नियंत्रण प्रदर्शित करता है। 5 जनवरी 2026 का ऑपरेशन—सैन्य हमलों के साथ राज्य प्रमुख की बलपूर्वक बर्खास्तगी को मिलाकर—इस परिभाषा को पूरा करता है, जेनेवा कन्वेंशन के तहत दायित्वों को ट्रिगर करता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून स्पष्ट है: कब्जा करने वाली शक्ति अपने लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं कर सकती। हेग विनियमों के अनुच्छेद 55 कब्जाधारी को usufruct तक सीमित करता है—गैर-नवीकरणीय संसाधनों के depletion के बिना अस्थायी प्रशासन। चौथे जेनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 33 स्पष्ट रूप से लूट को प्रतिबंधित करता है, ऐसे शोषण को रोम

संविधि के तहत युद्ध अपराध वर्गीकृत करता है। ट्रंप के वादे कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल से लाभान्वित होंगी, और राजस्व अमेरिकी लागतों की भरपाई करेंगे, इन निषेधों का उल्लंघन करने के स्पष्ट इरादे का संकेत देते हैं।

एक राज्य प्रमुख का अपहरण

निकोलास मदुरो की गिरफ्तारी इन उल्लंघनों को बढ़ाती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट मामले (2002) में पुष्टि की गई रिवाजी अंतरराष्ट्रीय कानून, बैठे राज्य प्रमुखों को विदेशी आपराधिक क्षेत्राधिकार से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करता है। मदुरो को सहमति या प्रत्यर्पण के बिना बलपूर्वक हटाना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का उल्लंघन करता है, जो राज्य की संप्रभुता के खिलाफ बल के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। कानूनी विद्वान चेतावनी देते हैं कि यह कार्य राज्य जिम्मेदारी, क्षतिपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जांच को आमंत्रित करता है, जबकि वैश्विक रूप से कूटनीतिक मानदंडों को कमजोर करने वाला मिसाल कायम करता है।

अमेरिकी कानून अनदेखा

घरेलू स्तर पर, हस्तक्षेप 1973 के युद्ध शक्ति संकल्प से टकराता है। राष्ट्रपति अमेरिकी सेनाओं को शत्रुताओं में तभी शामिल कर सकता है जब कांग्रेस की अनुमति हो या अमेरिका पर हमले से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल हो। ट्रंप का “नार्को-आतंकवाद” औचित्य इस मानक को पूरा नहीं करता। कोई आसन्न सशस्त्र हमला नहीं था। इसलिए ऑपरेशन शत्रुताओं की अवैध शुरुआत था, कांग्रेस को दरकिनार करके और 2011 की लीबिया जैसी पिछली हस्तक्षेपों की विवादों की गूंज।

फिलिस्तीन और वेनेजुएला: एक ही अपराध, अलग नाम

ये उल्लंघन फिलिस्तीनी संसाधनों के इज़राइल के लंबे समय से चल रहे शोषण को प्रतिबिंबित करते हैं। वेस्ट बैंक में, इज़राइल साझा जलभृत के अनुमानित 80% जल को बस्तियों और घरेलू उपयोग के लिए मोड़ता है, फिलिस्तीनी पहुंच को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है—कब्जा कानून का एक और उल्लंघन। गाजा में, फिलिस्तीनियों के प्राकृतिक गैस पर नियंत्रण की इज़राइल की बाधा, साथ ही दिसंबर 2025 में मिस्र के साथ हस्ताक्षरित \$35 अरब निर्यात सौदा, आर्थिक वर्चस्व को मजबूत करता है जबकि फिलिस्तीनी वंचित रहते हैं।

वेनेजुएला में जैसे, कब्जा केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि लाभ के लिए कायम है।

निष्कर्ष

मदुरो का वेनेजुएला और फिलिस्तीन का जोड़ना न तो अतिशयोक्ति था न प्रचार—यह निदान था। दोनों समाज, मूल्यवान जीवाश्म ईंधनों से संपन्न, संप्रभुता का दावा करने के लिए दंडित किए गए हैं। दोनों ने नाकाबंदियां, प्रतिबंध और सैन्य बल का सामना किया है जो प्रतिरोध तोड़ने और संसाधन निकासी सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जब तक तेल और गैस वैश्विक शक्ति का आधार बने रहेंगे, साम्राज्यवादी लालच मानवीय हस्तक्षेप के रूप में छिपता रहेगा।

न्याय को बयानबाजी से अधिक की मांग है। यह कब्जों का अंत, संसाधन संप्रभुता की बहाली, और आधुनिक संघर्ष को चलाने वाले ऊर्जा साम्राज्यवाद का सामना करने की मांग करता है। मदुरो को चुप कराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो सत्य व्यक्त किया वह कायम है—और जिस साझा संघर्ष का उन्होंने नाम दिया वह भी।